



2026:AHC:22292-DB

ए.एफ.आर.

निर्णय सुरक्षित : 22.01.2026

निर्णय प्रदत्त : 02.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या-1565 वर्ष 1987

अच्छाईबार एवं अन्य

.....अपीलकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्तागण के अधिवक्ता : श्री जयप्रकाश नारायण राज, श्री कमलेश्वर सिंह, श्री प्रमोद शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : —

न्यायालय संख्या – 48

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र धारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति चावन प्रकाश

(माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र धारी सिंह द्वारा प्रदत्त)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1. यह आपराधिक अपील, बस्ती के सेशन जज द्वारा एसटी संख्या 184/1985 (पुलिस स्टेशन बखिरा, जिला बस्ती) में 27.05.1987 के फैसले और 01.06.1987 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। इस फैसले में सेशन जज ने सभी अपीलकर्ताओं – अच्छाइबार (राम अच्छाइबार), फूलमन, संवारे, राजेंद्र और राम दास – को आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 149 के तहत दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा, आरोपी अच्छाइबार, राम दास, फूलमन और संवारे को आईपीसी की धारा 147 के तहत दोषी ठहराया गया और एक साल की कठोर सजा सुनाई गई, जबकि आरोपी राजेंद्र को आईपीसी की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया और दो साल की कठोर सजा सुनाई गई।

2. हालाँकि, सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।

संक्षिप्त तथ्य

3. इस अपील का आधार बनने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं: पहली सूचना देने वाली श्रीमती मुर्ता (जो गजाउली गाँव की निवासी और बीदेशी कुर्मी की पत्नी हैं) ने 07.04.1985 को सुबह 09:30 बजे बखिरा पुलिस स्टेशन में एक लिखित रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया कि पिछली रात उनके पति खाना खाने के बाद खलिहान में अपनी ज़मीन (चक) के हिस्से में सोए थे। चक के पास ही वह भी एक छप्पर के नीचे सोई थीं। उनकी बेटियाँ गाँव में अपने घर पर थीं। उनका चक आबादी के पश्चिम में सटा हुआ है। वह और आरोपी-अच्छाइबार आपसी बँटवारे के कारण एक ही घर के अलग-अलग हिस्सों में रहते थे। आरोपी-राजेंद्र (राम दास उर्फ लल्ला का बेटा) बगल वाले घर में रहता था। FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके घर का छप्पर मरम्मत और बदलाव के लिए गिराया गया था। उस समय, एक तरफ उनके पति और दूसरी तरफ अच्छाइबार और उसके दो बेटों (साँवरें और फूलमन) के बीच कुछ कहा-सुनी हुई थी। आरोपियों का साथ देते हुए राजेंद्र और उसके पिता लल्ला भी वहाँ आए और उनके पति को गालियाँ दीं और बुरा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अंजाम भुगतने की धमकी दी। आज सुबह लगभग 03:00-03:30 बजे, ऊपर बताए गए सभी आरोपी खलिहान में उनके पति के पास आए और लाठी और चाकू से उन पर हमला करने लगे। पति की दर्द भरी चीखें सुनकर वह जाग गई, मौके पर पहुँची और मदद के लिए शोर मचाया। नरेश (बंशराज का बेटा) और राम शंकर (गंगा का बेटा), जो पास के खेत और खलिहान में थे, और गाँव के कुछ अन्य लोग मौके पर पहुँचे। गवाहों के आने और उन्हें ललकारने पर, आरोपी गालियाँ देते और धमकियाँ देते हुए वहाँ से भाग गए। आरोपी-राजेंद्र के पास चाकू था, जबकि आरोपी-अच्छाड़वार, साँवरें, फूलमन और राम दास के पास लाठियाँ थीं। डर के कारण उनका पीछा नहीं किया जा सका और वे भागने में सफल रहे। चाँदनी रात में गवाहों ने आरोपियों को देखा और पहचाना। लाश को घटनास्थल पर ही छोड़कर, उसने पुलिस स्टेशन में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श.का-2) जमा की।

4. ऊपर बताई गई रिपोर्ट के आधार पर, बखीरा पुलिस स्टेशन (ज़िला बस्ती) में आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149 और 302 के तहत वाद अपराध संख्या 57/1985 (प्रदर्श.का-3) दर्ज किया गया। इसे हेड मुहर्रिर पीडब्लू-5 राम जतन चौधरी ने सुबह 09:30 बजे रिपोर्ट संख्या 12 के ज़रिए जीडी में दर्ज किया।

5. FIR दर्ज होने के बाद, कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और मामले की जांच पीडब्लू-8, एसआई विजय प्रताप सिंह को सौंपी गई। वे सुबह 11:05 बजे घटना स्थल पर पहुँचे और गजाउली गाँव में पश्चिम की ओर स्थित बिदेशी (जिन्हें आगे "मृतक" कहा गया है) के खेत (चक) में उनकी लाश पड़ी पाई। उस खेत के एक हिस्से में खलिहान था और वहाँ भूसे (कूटी) का ढेर लगा था। लाश उसी भूसे पर पड़ी थी। मृतक की पत्नी, जो इस मामले की पहली सूचना देने वाली (सूचनाकर्ता) हैं, चौकीदार राम राज के साथ लाश के पास मौजूद थीं। उन्होंने लाश को अपने कब्जे में लिया और

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जाँच-पड़ताल (इनक्वेस्ट) की, जिसे प्रदर्श.का -8 के तौर पर दर्ज किया गया। उन्होंने लाश की फ़ोटो और चालान (लाश का चालान) भी तैयार किया, जो प्रदर्श.का 9 और 10 हैं। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए सीएमओ को पत्र भी लिखा। इसके बाद जाँच अधिकारी ने सीलबंद लिफ़ाफ़े में लाश को कॉन्स्टेबल राजेंद्र प्रताप यादव और संग्राम प्रसाद को सौंप दिया, साथ ही एफआईआर की कॉपी और सील का नमूना जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ भी दिए। पहली सूचना देने वाली श्रीमती मुर्ता और गवाहों के बताए अनुसार, उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया और साइट प्लान (घटना स्थल का नक्शा) तैयार किया, जो प्रदर्श.का 14 है। उन्हें घटना स्थल पर गेहूँ के ताज़े भूसे के ढेर पर खून मिला। उन्होंने उसका और सामान्य भूसे का नमूना लिया, उन्हें सीलबंद लिफ़ाफ़े में रखा और उनके मेमो तैयार किए, जिन्हें प्रदर्श.का-15 के तौर पर चिह्नित किया गया। उन्हें 'कथरी' (बिछौने) पर भी खून मिला। उन्होंने खून से सनी कथरी और रज़ाई का एक टुकड़ा लिया, उन्हें सीलबंद लिफ़ाफ़े में रखा और मेमो प्रदर्श.का-16 तैयार किया और खून से सनी ये सभी चीज़ें फ़ोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, आगरा भेज दीं। उन्होंने घटना स्थल पर पहली सूचना देने वाली का बयान भी दर्ज किया।

6. 08.04.1985 को, मामले की जाँच स्टेशन हाउस ऑफ़िसर (एसओ) जय प्रकाश मिश्रा ने अपने हाथ में ले ली।

7. पीडब्लू-7, स्टेशन हाउस ऑफ़िसर जय प्रकाश मिश्रा ने गवाहों नरेश और राम शंकर वगैरह के बयान दर्ज किए।

08.04.1985 को सूचनाकर्ता की सूचना पर, उन्होंने आरोपी अच्छाड़बार को समी उल्लाह के ईट-भट्टे के पास से गिरफ़्तार किया। आरोपी की धोती और बनियान पर ताज़े खून के धब्बे थे। उसकी लाठी पर भी खून के धब्बे थे। उन्होंने इन सभी चीज़ों को ज़ब्त कर लिया और मेमो प्रदर्श.का 5 तैयार किया। वे चीज़ें, यानी धोती, बनियान और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लाठी का टुकड़ा, प्रदर्श.का 1, 2 और 3 हैं। 10.04.1985 को, उन्होंने बाकी आरोपियों के खिलाफ धारा 82/83 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यायालय को रिपोर्ट दी। 12.04.1985 को, उन्होंने आरोपियों के ठिकानों पर छापा मारा, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 13.04.1985 को, उन्होंने आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार किया, जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया और हमले में इस्तेमाल हथियार बरामद करवाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद, पुलिस उसे उसके घर ले गई, जहाँ उसने खपरैल (छत) से चाकू निकाला और पुलिस को सौंप दिया (प्रदर्श.का-61)। आरोपी राजेंद्र ने जो शर्ट पहनी थी, उस पर भी खून के धब्बे थे। उन्होंने उसे ज़ब्त कर लिया, उसका मेमो (प्रदर्श.का -5) तैयार किया और उसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, आगरा भेज दिया।

8. जांच पूरी होने के बाद, जांच अधिकारी ने आरोपी अच्छाड़वार, संवारे, फूलमन, राजेंद्र और राम दास के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

9. चूँकि यह वाद विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, अतः विद्वान मजिस्ट्रेट ने वाद को सत्र न्यायालय के सुपुर्द (Committed) कर दिया, जहाँ इसका पंजीकरण सत्र परीक्षण संख्या 184 वर्ष 1985 के रूप में किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश, बस्ती ने अभियुक्तगण अच्छाड़वार, सांवरे, फूलमन, राजेन्द्र तथा रामदास के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 तथा धारा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत आरोप विरचित किए। अभियुक्त राजेन्द्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत पृथक रूप से भी आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाए गए तथा समझाए गए, जिन्हें उन्होंने अस्वीकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण की माँग की।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. अपील करने वाले के अपराध को पूरी तरह साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने तथ्यों से जुड़े आठ गवाहों से पूछताछ की। इनमें से पीडब्लू-2, श्रीमती मुर्ता (मामले की पहली सूचना देने वाली), पीडब्लू-3 शंकर, पीडब्लू-4 राम नरेश और पीडब्लू-6 इकबाल हुसैन तथ्यों के गवाह थे। वहीं, पीडब्लू-1 डॉ. पी.एन. बंसल (जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया), पीडब्लू-5 हेड कॉन्स्टेबल 69 राम जतन चौधरी (एफआईआर लिखने वाले), पीडब्लू-7 एसएचओ जय प्रकाश मिश्रा (दूसरे जांच अधिकारी) और पीडब्लू-8 एसआई विजय प्रताप सिंह (जिन्होंने जांच शुरू की थी) औपचारिक गवाह थे।

11. पीडब्लू-1 डॉ. पी.एन. बंसल ने 08.04.1985 को शाम 04:00 बजे मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। शव को कॉन्स्टेबल राजेंद्र प्रसाद यादव और संग्राम प्रसाद ने सीलबंद हालत में पहुंचाया था। बाहरी जांच में डॉक्टर ने मृतक की उम्र लगभग 55 साल पाई। मौत के समय और पोस्टमार्टम के बीच लगभग 36 घंटे का अंतर था। मृतक औसत कद-काठी का व्यक्ति था। शरीर के ऊपरी और निचले अंगों में 'रिगोर मोर्टिस' (मौत के बाद शरीर का अकड़ना) की स्थिति खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर को मौत से पहले लगी निम्नलिखित चोटें मिलीं।

1. चेहरे के बाईं ओर, ठुड़ी से लगभग 3 सेंटीमीटर बगल में, 6 सेमी x 4 सेमी का घाव जो हड्डी तक गहरा है; इसके नीचे जबड़े की हड्डी कई टुकड़ों में टूटी हुई है।

2. निचले होंठ पर 4 सेमी x 3 सेमी का घाव जो हड्डी तक गहरा है; नीचे का दांत टूटा हुआ और बाहर निकला हुआ है, और जबड़े की हड्डी कई टुकड़ों में टूटी हुई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. ऊपरी होंठ पर 4 सेमी x 3 सेमी का फटा हुआ घाव जो हड्डी तक गहरा है; नीचे का दांत बाहर निकल आया है और ऊपरी जोड़ कई टुकड़ों में टूट गया है।

4. चेहरे के दाहिने हिस्से में नाक की जड़ के पास 4 सेमी x 1 सेमी का छेद वाला घाव जो हड्डी तक गहरा है; नीचे की हड्डी टूट गई है।

5. माथे के बाईं ओर, बाईं भौंह के ऊपर 4 सेमी x 2 सेमी का छेद वाला घाव जो हड्डी तक गहरा है; नीचे ऑर्बिट (आंख का गड्ढा) है। पैरिएटल हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई है।

6. माथे के दाहिने हिस्से में नाक की जड़ से 2 सेमी ऊपर 4 सेमी x 2 सेमी का फटा हुआ घाव जो हड्डी तक गहरा है; नीचे की हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई है।

7. माथे के दाहिने हिस्से में 4 सेमी x 3 सेमी का छेद वाला घाव जो हड्डी तक गहरा है; दाहिनी भौंह का ऑर्बिट और पैरिएटल हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई हैं।

8. चेहरे के दाहिने हिस्से पर 15 सेमी x 10 सेमी का कई जगहों पर रगड़ और चोट का निशान; यह आंख के नीचे 4 सेमी और दाहिने कान के ठीक नीचे है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. चेहरे के बाईं ओर 20 सेमी x 12 सेमी का कई जगहों पर रगड़ और चोट का निशान; यह बाएं कान के ठीक नीचे और बाईं आंख के नीचे 5 cm पर है।

12. अंदरूनी जांच में डॉक्टर को खोपड़ी में खून का थक्का मिला। झिल्लियां सूजी हुई और फटी हुई थीं। खून का थक्का मौजूद था, दिमाग सूजा हुआ और फटा हुआ था और खून का थक्का मौजूद था; मुंह, दांत और जीभ टूटे हुए थे; पेट में आधा पचा हुआ चावल का खाना था। डॉक्टर की राय में, मरने वाले की मौत मरने से पहले लगी चोटों के कारण शॉक और खून बहने से हुई। डॉक्टर की राय में, चोट संख्या 4, 5 और 7 धारदार हथियार से लगी हो सकती थीं। बाकी चोटें लाठी के पिछले हिस्से (हुरा) या किसी और कुंद चीज से लाठी मारने पर लगी हो सकती थीं। उन्होंने यह भी राय दी कि मरने वाले की मौत खाना खाने के 4-5 घंटे बाद हुई।

13. पीडब्लू-2, श्रीमती मुर्ता, जो मामले की पहली सूचना देने वाली और मृतक की पत्नी हैं, ने 02.07.1986 को दर्ज अपने मुख्य बयान में कहा कि शिव सरन, सूरजबली और जय करन सगे भाई हैं। विदेशी, शिव सरन का बेटा है, जबकि अच्छाड़बार, सूरजबली का बेटा है। अच्छाड़बार के बेटे फूलमन और संवारे हैं। जयकरण का बेटा रामदास है और रामदास का बेटा राजेंद्र है। पीडब्लू-2, श्रीमती मुर्ता ने आगे बताया कि उनका केवल एक बेटा और दो बेटियां हैं। गांव में उनका पुश्तैनी घर है। उस घर में वह अपने परिवार (मृतक सहित) के साथ रहती हैं, जबकि सूरजबली और जयकरण अपने परिवारों के साथ अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं। पति की हत्या से दो दिन पहले, मृतक के घर के एक हिस्से की छत को दोबारा छप्पर डालने के लिए गिराया गया था। उस समय आरोपियों और मृतक के बीच कुछ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कहा-सुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपियों ने मृतक को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। आरोपी मृतक को घर में हिस्सा नहीं देना चाहते थे। पश्चिम की ओर लगभग दो बीघा की दूरी पर, उनका तीन बीघा का एक चक (खेत का टुकड़ा) था। उस चक में उन्होंने एक मड़ाई (झोपड़ीनुमा शेड) बनाई थी, जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। घटना की तारीख से एक साल से भी पहले, मृतक काम करने के बाद खलिहान में सो गया था। छप्पर के अंदर वह भी सो रही थी। गवाह ने आगे बताया कि वह और उनके पति (मृतक) आधी रात तक खलिहान में काम करते थे और उसके बाद खाना खाकर सो जाते थे। वह चांदनी रात थी। मृतक ने चावल, दाल और आलू का चोखा खाया था। रात करीब 2:00 बजे, आरोपी लल्ला उर्फ रामदास, फूलमन, संवारे, अच्छाइबार और राजेंद्र वहां आए। राजेंद्र के पास चाकू था और बाकी आरोपियों के पास लाठियां थीं। अच्छाइबार ने उनके पति को काबू किया और उनकी छाती पर बैठ गया, राजेंद्र ने चाकू से हमला किया, जबकि संवारे, फूलमन और लल्ला ने लाठियों के पिछले हिस्से से हमला किया। उनके शोर मचाने पर गवाह शंकर और नरेश मौके पर दौड़े। गवाहों को घटना स्थल की ओर आते देख, आरोपी उनके पति की हत्या करके भाग गए। उनके पति की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह-सुबह गांव के प्रधान, चौकीदार और गांव के कई लोग वहां आए। उन्होंने इसकी रिपोर्ट... प्रधान इकबाल हुसैन ने अपराध का विवरण लिखकर उसे पढ़कर सुनाया, जिस पर उसने अपना अंगूठे का निशान लगाया और शंकर के ज़रिए उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया।

14. पीडब्लू-3, शंकर ने अपनी मुख्य गवाही में, जो 08.07.1986 को दर्ज की गई थी, कहा कि उसका घर मृतक के खलिहान से पूर्व की ओर लगभग 25 कड्डा की दूरी पर है। उसके घर और मृतक के खलिहान के बीच कोई घर नहीं है। लगभग डेढ़ साल पहले, सुबह करीब 3:00 बजे, वह अपने खलिहान में लेटा हुआ था, जो उसके घर के सामने है और मृतक के खलिहान से 35 कड्डा की दूरी पर है। श्रीमती मुर्ता की चीखें सुनकर कि "वे मार रहे हैं", वह मृतक के

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



खलिहान की ओर दौड़ा। वह उस जगह से लगभग 3 कद्दा दूर था और उसने देखा कि आरोपी-राजेंद्र चाकू लिए हुए था और अच्छाइबार, संवारे, फूलमन और राम दास लाठियों के पिछले हिस्से से मृतक पर हमला कर रहे थे। चाँदनी रात थी। मृतक की पत्नी रो रही थी। राम नरेश भी वहाँ पहुँच गया था। जब तक वे घटना स्थल से दो कद्दा दूर पहुँचे, तब तक आरोपी मृतक की हत्या करके उत्तर की ओर भाग चुके थे। उसके पास टॉर्च थी और वह उसकी रोशनी डाल रहा था। फिर, सुबह-सुबह जब गाँव के लोग वहाँ जमा हुए, तो मृतक की पत्नी ने प्रधान से घटना की रिपोर्ट लिखवाई, जो इस गवाह को पुलिस स्टेशन में देने के लिए सौंपी गई। आरोपी और मृतक एक ही इमारत में रहते थे। वे आपसी बँटवारे के आधार पर अलग-अलग रह रहे थे। घटना से तीन दिन पहले, मृतक ने मरम्मत के लिए अपनी छत (खपरैल) का एक हिस्सा गिरा दिया था। उस दिन आरोपियों ने मृतक को गाली दी थी और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। वह उस समय वहाँ मौजूद था। जब तक वह मृतक के पास पहुँचा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

15. पीडब्लू-4, राम नरेश ने अपनी मुख्य गवाही में, जो 09.07.1986 को दर्ज की गई थी, बताया कि मृतक की हत्या लगभग डेढ़ साल पहले हुई थी। यह फसल कटाई का मौसम था और चैत्र का महीना था। वह रात में खेत में सो रहा था। उस दिन उसने फसल काटी थी और उस फसल की सुरक्षा के लिए वह वहीं सो रहा था। सुबह लगभग 3:30 बजे, मृतक की पत्नी ने "बचाओ-बचाओ" की आवाज़ लगाई। वह उस समय तक सोया नहीं था। उसने आवाज़ सुनी और घटनास्थल पर गया। वहाँ पहुँचने पर, उसने देखा कि मृतक अपने खलिहान में कूटी और गेहूँ पर पड़ा था और आरोपी राजेंद्र चाकू से, तथा राम दास, फूलमन, साँवरे और अच्छाइबार लाठी के पिछले हिस्से से मृतक पर हमला कर रहे थे। चाँदनी रात थी। शंकर भी घटनास्थल पर पहुँच गया था। जब वह उस जगह पहुँचा और मृतक से लगभग डेढ़ कद्दा की दूरी पर था, तो आरोपी मृतक की हत्या करके भाग गए। उसके हाथ में टॉर्च थी। वह उनका पीछा करना

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चाहता था, लेकिन चाकू और लाठियों के डर से उसने उनका पीछा नहीं किया। आरोपियों के घटनास्थल से चले जाने के बाद, उसने देखा कि मृतक की मौत हो चुकी थी। जिस खेत में वह उस समय सो रहा था, वह घटनास्थल से दक्षिण-पश्चिम दिशा में 20-25 कद्दा की दूरी पर है।

16. पीडब्लू-5, हेड कॉन्स्टेबल राम जतन चौधरी ने अपनी मुख्य गवाही में बताया कि 07.04.1985 को वे बखीरा पुलिस स्टेशन में हेड मुहरीर के पद पर तैनात थे। उस तारीख को उन्होंने शंकर लाल द्वारा लाई गई रिपोर्ट के आधार पर चिक एफआईआर, प्रदर्श.का -3 तैयार की थी, जिसे जीडी में रिपोर्ट संख्या 12 के तहत सुबह 09:30 बजे दर्ज किया गया था।

17. पीडब्लू-6, इकबाल हुसैन ने अपनी मुख्य गवाही में, जो 18.07.1986 को दर्ज की गई थी, बताया कि वे गजौली के ग्राम प्रधान हैं। जिस गाँव में वे रहते हैं और गजौली गाँव एक ही ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। 07.04.1985 की सुबह, मृतक की पत्नी श्रीमती मुर्ता के कहने पर, उन्होंने रिपोर्ट लिखी और पढ़कर सुनाई; रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद, उन्होंने इसे शंकर को पुलिस स्टेशन में देने के लिए सौंप दिया। दरोगा जी (पुलिस इंस्पेक्टर) गाँव आए और जाँच (इनक्वेस्ट) की, जिस पर उन्होंने भी अपने हस्ताक्षर किए। पुलिस इंस्पेक्टर ने खून से सने गेहूँ के भूसे (कुट्टी), सादे भूसे, खून से सनी कथरी, रजाई और टाट भी इकट्ठा किए और उनके मेमो बनाए, जिन पर इस गवाह ने भी हस्ताक्षर किए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. पीडब्लू-8, SI विजय प्रताप सिंह, जिन्होंने शुरुआती जाँच की थी, और पीडब्लू-7, एसओ जय प्रकाश मिश्रा, जिन्होंने बाकी जाँच की और चार्जशीट दाखिल की, उनके सबूतों पर ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

19. अभियोजन पक्ष के सबूत पूरे होने के बाद, अभियुक्तों के बयान सीआर.पी.सी. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें सभी अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि गवाह दुश्मनी के कारण उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। हालाँकि, उन्होंने मुकदमे का सामना करने की बात कही।

20. अभियुक्त-अच्छाड़बार ने आगे कहा कि उसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उसकी शर्ट ले ली थी। उससे लाठी बरामद नहीं हुई थी। उसने यह भी कहा कि जब उसे गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस ने उसकी शर्ट पर नेल पॉलिश छिड़क दी थी। 21. आरोपी ने अपने बचाव में राजा राम को डीडब्ल्यू-1 के तौर पर पेश किया है।

22. डीडब्ल्यू-1, राजा राम ने अपनी मुख्य गवाही में कहा है कि वह गजराउली गाँव में रहते हैं। आरोपी और शिकायत करने वाले भी उसी गाँव में रहते हैं। पुलिस ने आरोपी से कोई चाकू बरामद नहीं किया।

पुलिस गाँव आई और एक खाली कागज़ पर उनका अंगूठे का निशान लिया।

23. बस्ती के विद्वान सेशन जज ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जाँच-परख करने के बाद, आरोपी-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और ऊपर बताई गई सज़ा सुनाई।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



24. इसलिए, यह अपील की गई है।

25. न्यायालय के 09.09.2025 के आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 1, 4 और 5 यानी अच्छाड़बार (राम अच्छाड़बार), राजेंद्र और राम दास की ओर से दायर अपील खत्म हो गई है, जबकि 13.01.2025 को अपीलकर्ता संख्या 2, फूलमन की अपील भी खत्म हो गई।

26. अब, यह न्यायालय अपीलकर्ता संख्या 3, संवारे की अपील पर फैसला कर रही है।

अपीलकर्ताओं की ओर से दलीलें

27. अपील करने वालों के अधिवक्ता का कहना है कि गवाहों के बयानों में अहम विरोधाभास हैं।

28. अपील करने वालों के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि पीडब्लू-3 शंकर और पीडब्लू-4 राम नरेश ने बयान दिया कि उनके पास टॉर्च थी, लेकिन जांच अधिकारी ने कोई मेमो नहीं बनाया।

29. अपील करने वालों के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि जांच में गड़बड़ी है क्योंकि जांच अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि जब उसने आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार किया तो उसके कपड़ों पर खून मिला था, जबकि आगरा की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में उसकी शर्ट पर कोई खून नहीं मिला, जिससे अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी गलत साबित हो गई।

30. अपील करने वालों के अधिवक्ता का आखिर में यह कहना है कि आरोपी राजेंद्र को चाकू से चोट पहुंचाने का काम सौंपा गया था, जबकि मौजूदा अपीलकर्ता को लाठी दी गई थी और ज्यादातर चोटें चाकू से लगी थीं, इसलिए अपीलकर्ता को मृतक की मौत का कारण बनी चोटों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

31. घटना रात में हुई थी और आरोपी को पहचानने के लिए रोशनी काफी नहीं थी।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

32. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने जिन विरोधाभासों की ओर इशारा किया है, वे बहुत मामूली हैं। विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता का यह भी कहना है कि घटना स्थल पर पहुँचने के समय पीडब्लू 3 और 4 के पास जो टॉर्च थी, उसका मेमो न बनाना जांच अधिकारी की चूक है, और इसका लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता।

33. उन्होंने यह भी बताया कि अपीलकर्ता के पास लाठी थी और ज्यादातर चोटें लाठी से ही लगी थीं। उनका यह भी कहना है कि चूँकि चाँदनी रात थी, इसलिए गवाह आरोपी को आसानी से पहचान सकते थे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



34. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री जय प्रकाश नारायण राज और राज्य की ओर से पेश विद्वान एजीए श्री एस.एन. तिवारी की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखा।

विश्लेषण और निष्कर्ष

35. अपीलकर्ता के अधिवक्ता की पहली दलील पीडब्लू-2 श्रीमती मुर्ता, पीडब्लू-3 शंकर और पीडब्लू-4 राम नरेश के बयानों में विरोधाभास के बारे में है। अधिवक्ता ने जो विरोधाभास बताए हैं, वे ये हैं कि पीडब्लू-1 श्रीमती मुर्ता ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी अच्छाइबार मृतक की छाती पर बैठा था और आरोपी राजेंद्र चाकू से मृतक पर हमला कर रहा था, जबकि संवारे, फूलमन और लल्ला लाठी के पिछले हिस्से से हमला कर रहे थे; वहीं पीडब्लू-3 शंकर और पीडब्लू-4 ने अपने बयानों में यह नहीं कहा कि श्रीमती मुर्ता की चीखें सुनकर जब वे मौके पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि आरोपी राजेंद्र चाकू से मृतक पर हमला कर रहा था, जबकि आरोपी अच्छाइबार, संवारे, फूलमन और राम दास लाठी से मृतक पर हमला कर रहे थे। हमने पीडब्लू-1 श्रीमती मुर्ता, पीडब्लू-3 शंकर और पीडब्लू-4 राम नरेश के बयानों को देखा है। पीडब्लू-1 श्रीमती मुर्ता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी अच्छाइबार मृतक की छाती पर बैठा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सिर्फ मृतक की छाती पर बैठा था; बल्कि वह यह कहना चाहती हैं कि आरोपी अच्छाइबार ने मृतक को काबू में कर लिया था, और यह न्यायालय उनके बयानों में कोई विरोधाभास नहीं देख पाया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



36. इसके अलावा, गवाहों के बयानों में हमेशा कुछ सामान्य अंतर हो सकते हैं। ये अंतर समय बीतने और घटना के समय सदमे और डर जैसी मानसिक स्थिति के कारण होते हैं। अहम अंतर वे होते हैं जो सामान्य नहीं होते और अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ पर असर डालते हैं, और जिनकी किसी सामान्य व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जाती। इसलिए, अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया ऐसा मामूली विरोधाभास अपीलकर्ता के किसी काम का नहीं है। साथ ही, अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताए गए अंतर बहुत मामूली हैं, जो किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले की नींव को प्रभावित नहीं करते हैं।

37. राजस्थान राज्य बनाम कल्की (1981) 2 एस सी सी 752 मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया कि पीडब्लू-1 एक 'बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाली' गवाह थी क्योंकि वह मृतक की पत्नी थी और उसके बयान में विसंगतियां थीं। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, राजस्थान राज्य ने एक आपराधिक अपील दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने पैराग्राफ 5, 6 और 7 में निम्नलिखित बातें कहीं:

5. जैसा कि उपरोक्त है, उच्च न्यायालय ने पी.डब्ल्यू. 1 के सबूतों पर भरोसा करने से दो आधारों पर इनकार कर दिया:

(1) वह एक "बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाली" गवाह थी क्योंकि वह "मृतक की पत्नी है", और (2) उसके सबूतों में विसंगतियां थीं। सम्मानपूर्वक, हमारी राय में, दोनों आधार गलत हैं। क्योंकि, मामले की परिस्थितियों में, वह एकमात्र और सबसे स्वाभाविक गवाह थी; घटना के समय झोपड़ी में मृतक के साथ मौजूद एकमात्र व्यक्ति वही थी, और घटना को देखने वाली भी वही एकमात्र व्यक्ति थी। यह सच है कि वह मृतक की पत्नी है; लेकिन उसे 'दिलचस्पी रखने वाली'

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गवाह नहीं कहा जा सकता। वह मृतक से संबंधित है। 'संबंधित' होना 'दिलचस्पी रखने वाले' होने के बराबर नहीं है। किसी गवाह को 'दिलचस्पी रखने वाला' तभी कहा जा सकता है जब उसे मुकदमे के नतीजे से कोई फायदा हो; जैसे किसी सिविल मामले में डिक्री से, या किसी आरोपी को सजा मिलते देखने से। कोई गवाह जो स्वाभाविक गवाह हो और मामले की परिस्थितियों में एकमात्र संभावित चश्मदीद गवाह हो, उसे 'दिलचस्पी रखने वाला' नहीं कहा जा सकता। इस मामले में, पी.डब्ल्यू. 1 की असली अपराधी को बचाने और प्रतिवादियों को झूठे मामले में फंसाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।

6. उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यू 1 के सबूतों पर भरोसा न करने का दूसरा कारण यह बताया कि उनमें "महत्वपूर्ण विसंगतियां" (सामग्री संबंधी विसंगतियां) थीं। जैसा कि उपरोक्त है, हमने पीडब्ल्यू 1 के सबूतों को देखा है। हमें उनके सबूतों में कोई "महत्वपूर्ण विसंगति" नहीं मिली। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने जिन विसंगतियों का जिक्र किया है, वे मामूली, महत्वहीन, स्वाभाविक और 'महत्वपूर्ण' नहीं हैं। ये विसंगतियां इस बारे में हैं कि किस आरोपी ने मृतक को ज़मीन पर दबाया और शरीर के किस हिस्से पर दबाया और शरीर के किस हिस्से पर बैठा; क्या प्रतिवादी कल्कि ने मृतक को कुल्हाड़ी से तब मारा जब वह खड़ा था या ज़मीन पर लेटा हुआ था, और क्या वार सिर की तरफ से किया गया था या पैरों की तरफ से। गवाहों के बयानों में हमेशा कुछ सामान्य विसंगतियां होती हैं, चाहे वे कितने भी ईमानदार और सच्चे क्यों न हों। ये विसंगतियां देखने में सामान्य गलतियों, समय बीतने के कारण याददाश्त की सामान्य गलतियों, घटना के समय सदमे और डर जैसी मानसिक स्थिति आदि के कारण होती हैं। महत्वपूर्ण विसंगतियां वे होती हैं जो सामान्य नहीं होतीं और जिनसे किसी सामान्य व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। जैसा कि उपरोक्त है, हमें पीडब्ल्यू 1 के सबूतों में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं मिली।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपील में केवल सबूतों का मूल्यांकन शामिल है और यह न्यायालय सबूतों के मूल्यांकन से निकले तथ्यों के निष्कर्षों में दखल नहीं दे सकता। यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील में यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यों के निष्कर्षों में दखल नहीं देता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि तथ्यों के निष्कर्ष गलत या तर्कहीन हैं और इनके परिणामस्वरूप न्याय नहीं हो पा रहा है तो यह न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने के लिए ऐसे निष्कर्षों को रद्द करने से इनकार नहीं करेगा।

38. 'स्टेट बनाम सरवनम और अन्य' (2008) 17 एस सी सी 587 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सबूतों पर विचार करते समय, न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या विरोधाभास या कमियां इतनी बड़ी थीं कि वे मुकदमे पर असर डाल सकती हैं। मामूली विरोधाभास, विसंगतियां, या छोटी-मोटी बातों में बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें या सुधार—जिनसे अभियोजन पक्ष के मुख्य मामले पर कोई असर न पड़े—उन्हें सबूतों को पूरी तरह से खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय को सारे सबूत देखने के बाद गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में अपनी राय बनानी चाहिए, और अपीलीय न्यायालय के लिए बिना किसी ठोस कारण के उस राय की दोबारा समीक्षा करना सही नहीं होगा।

39. 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम.के. एंथनी' (1985) 1 एस सी सी 505 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"गवाह की गवाही पर विचार करते समय, यह देखना जरूरी है कि क्या पूरी गवाही सुनने पर वह सच लगती है। एक बार जब यह धारणा बन जाती है, तो न्यायालय के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह गवाही की बारीकी से जांच करे। इसमें गवाही में बताई गई कमियों और खामियों को ध्यान में रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या वे गवाह की गवाही के मुख्य भाव के खिलाफ हैं और क्या इससे गवाही पर भरोसा करने लायक नहीं रह जाती। छोटी-मोटी बातों पर मामूली अंतर, गवाही से संदर्भ से हटकर वाक्य चुनना, या जांच अधिकारी की किसी ऐसी तकनीकी गलती को ज्यादा महत्व देना जो मामले की जड़ से जुड़ी न हो – इन आधारों पर आम तौर पर पूरी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। जिस न्यायालय में गवाह ने गवाही दी, उसे गवाह की गवाही के मुख्य भाव के बारे में राय बनाने का मौका मिला था; इसलिए, अपीलीय न्यायालय (जिसे यह मौका नहीं मिला) को विचारण न्यायालय द्वारा गवाही के मूल्यांकन को उचित महत्व देना होगा। जब तक कोई ठोस और मजबूत कारण न हों, तब तक छोटी-मोटी बातों या विवरणों में मामूली अंतर या खामियों के आधार पर गवाही को खारिज करना सही नहीं होगा। ईमानदार और सच्चे गवाह भी मुख्य घटना से जुड़ी न होने वाली कुछ बातों में अलग-अलग राय रख सकते हैं क्योंकि लोगों की देखने, याद रखने और बताने की क्षमता अलग-अलग होती है। जिरह एक गांव के व्यक्ति और एक मंझे हुए अधिवक्ता के बीच असमान मुकाबला होता है। इस गवाह (जो परिवार का दोस्त और शुभचिंतक है) की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद—जिसमें प्रतिवादी के अधिवक्ता की टिप्पणियों और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी गवाही को खारिज करने के कारणों को उचित महत्व दिया गया है, और साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा इस गवाह की गवाही के मूल्यांकन को भी ध्यान में रखा गया है—हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय ने गवाह नायर की गवाही को खारिज करने में गलती की, क्योंकि उनकी गवाही हमें भरोसेमंद और विश्वसनीय लगती है।"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



40. इसके अलावा, हम पाते हैं कि पीडब्लू-2, श्रीमती मुर्ता, जो इस मामले की पहली सूचना देने वाली हैं, अनपढ़ और गाँव की रहने वाली हैं। उनके बयान से यह साफ़ है कि उन्होंने पीडब्लू-6, इक़बाल हुसैन से रिपोर्ट लिखवाई थी और उस पर अपना अंगूठे का निशान लगाया था। इसलिए, ऐसी मामूली विरोधाभासी बातें अपील करने वाले के किसी काम की नहीं हैं।

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिवाजी बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1973 एससी 2622** मामले में यह कहा था:

"हत्या की घटना ग्रामीण इलाके की है, मामले के गवाह भी ग्रामीण हैं, इसलिए उनके व्यवहार और चीजों को देखने-समझने के तरीके को उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। इंसानी व्यवहार के बारे में अवास्तविक धारणाओं पर आधारित न्यायालयों के बहुत ज़्यादा परिष्कृत तरीके, जाहिर हैं, हमारे गांवों के सुस्त जीवनशैली वाले लोगों पर लागू नहीं किए जा सकते। अलग-अलग गवाहों के सबूतों की जांच करते समय, हमें यह ध्यान रखना होगा कि छोटी-मोटी बातों में अंतर, विवरणों में विसंगतियां, बयानों में विरोधाभास और मुख्य हिस्सों में बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई बातें गवाही के मूल सच को कमज़ोर नहीं करतीं, बशर्ते गवाही के मुख्य हिस्से में सच्चाई की छाप और संभावनाओं का मेल हो।"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



42. अपीलकर्ता के अधिवक्ता की दूसरी दलील यह है कि पीडब्लू-3 शंकर और पीडब्लू-4 राम नरेश ने बयान दिया कि उनके पास टॉर्च थी, लेकिन जांच अधिकारी ने कोई मेमो नहीं बनाया; इस दलील में कोई दम नहीं है क्योंकि अगर आरोपी ने टॉर्चलाइट का इस्तेमाल किया होता या घटना के समय पीड़ित के पास टॉर्चलाइट होती, या गवाहों ने कहा होता कि उन्होंने टॉर्चलाइट की रोशनी में आरोपी या घटना को देखा, तो इस बात पर जोर देने में दम होता कि जांच अधिकारी को उसे ज़ब्त करना चाहिए था क्योंकि इसे विचारण के दौरान एक अहम सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इस मामले में, पीडब्लू-3 शंकर और पीडब्लू-4 राम नरेश ने सिर्फ़ इतना कहा है कि उनके पास टॉर्च थी और उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने टॉर्चलाइट की रोशनी में आरोपी को देखा। इसलिए, टॉर्च को ज़ब्त न करना और मेमो न बनाना जांच अधिकारी की तरफ़ से कोई चूक नहीं मानी जा सकती।

43. अपीलकर्ता के अधिवक्ता की अगली दलील यह है कि जांच में गड़बड़ी थी। यह बताना ज़रूरी है कि इस मामले में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, आगरा की 13.08.1986 की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अच्छाड़बार की बनियान और आरोपी राजेंद्र की शर्ट पर कोई खून नहीं मिला था। सीआर.पी.सी.की धारा 313 के तहत अपने बयान में आरोपी अच्छाड़बार ने कहा है कि उसके कपड़ों पर नेल पॉलिश छिड़की गई थी। जांच अधिकारी से जिरह के दौरान यह बात नहीं पूछी गई। सिर्फ़ इसलिए कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने यह राय दी है कि आरोपी अच्छाड़बार की बनियान पर कोई खून नहीं मिला, यह नहीं कहा जा सकता कि जांच में गड़बड़ी थी, खासकर तब जब रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि गिरफ्तारी के समय अच्छाड़बार के कपड़ों पर कुछ तरह के दाग थे। अभियोजन पक्ष ने कपड़ों पर लगे उन दागों को खून के दाग बताया, जबकि आरोपी अच्छाड़बार ने कहा कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उसके कपड़ों पर नेल पॉलिश छिड़की थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



44. इसके अलावा, आरोपी की धोती, जिसे जांच अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया था और केमिकल जांच के लिए भेजा था, उसमें बेंज़िडाइन टेस्ट पॉज़िटिव पाया गया। साथ ही, चाकू और लाठी के एक हिस्से में भी बेंज़िडाइन टेस्ट पॉज़िटिव पाया गया। चूंकि विचारण के दौरान अपील करने वालों का नाम खास तौर पर लेने के मामले में चश्मदीद गवाहों के बयान एक जैसे रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि आरोपियों का अपराध साबित करने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं। जब पीडब्लू-2 श्रीमती मुर्ता, पीडब्लू-3 शंकर और पीडब्लू-4 राम नरेश की गवाही को एक साथ देखा जाता है, तो उनके बयान एक-दूसरे की पुष्टि करते हुए नज़र आते हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि जांच में कोई गड़बड़ी थी।

45. कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि जांच में कुछ कमियों के कारण आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों में इस पहलू पर विचार किया गया है।

46. सी मुनियाप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 9 एस सी सी 563 मामले में निम्नलिखित चर्चा और निष्कर्ष प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैं:

"55. किसी मामले में जांच में बहुत ज़्यादा कमियां हो सकती हैं। हालांकि, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या जांच अधिकारी (IO) से कोई चूक हुई है और क्या ऐसी चूक के कारण आरोपी को कोई फ़ायदा दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर कानून साफ़ है कि जांच में कमी अपने आप में बरी करने का आधार नहीं हो सकती। अगर ऐसी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जानबूझकर की गई या लापरवाही भरी जांच, या सतही जांच की वजह से हुई चूक या कमियों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, तो आपराधिक न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा और विश्वास कम हो जाएगा। जहां जांच एजेंसी की तरफ से लापरवाही या कमियां आदि हुई हों, जिसके परिणामस्वरूप जांच में खामियां रह गई हों, वहां न्यायालय की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह ऐसी चूक के बावजूद अभियोजन पक्ष के सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उक्त सबूत भरोसेमंद हैं या नहीं और किस हद तक भरोसेमंद हैं, और क्या ऐसी चूक ने सच्चाई का पता लगाने के मकसद को प्रभावित किया है। इसलिए, आपराधिक मुकदमे में न्यायिक जांच का एकमात्र दायरा जांच नहीं है। मामले में मुकदमे के नतीजे को केवल जांच की निष्पक्षता पर निर्भर नहीं रहने दिया जा सकता।"

47. दयाल सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य, (2012)8 एस सी सी 263 मामले में, सी. मुनियाप्पन (उपरोक्त) मामले में तय किए गए सिद्धांतों को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा:

"सिर्फ इसलिए कि पीडब्लू 3 और पीडब्लू 6 कानून की जरूरतों के मुताबिक अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे हैं, और जांच में कुछ कमी रह गई है, इससे आरोपी व्यक्तियों को इतना फायदा नहीं मिलेगा कि वे इस आधार पर बरी होने के आदेश के हकदार हो जाएं। ..."

गाजू बनाम उत्तराखंड राज्य (गजू बनाम उत्तराखंड राज्य) मामले में, उसी सिद्धांत को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर जांच में कोई कमी है, तो उसे न्यायालय द्वारा तब तक अहम नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वह अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ पर असर न डाले और आरोपी के लिए नुकसानदेह न हो। चूंकि न्यायालय ने जांच में कमी और उसके नतीजों से जुड़े पहले के सभी फैसलों पर गौर किया है, इसलिए उन मामलों में तय किए गए सिद्धांतों का जिक्र करना उपयोगी होगा:

48. एडवोकेट दिनेशन् उर्फ पी. दिनेशन् और अन्य बनाम केरल राज्य (2025) 3 एस सी सी 273 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर कई फैसलों पर विचार करने के बाद यह कहा:

"इसलिए, कानून का सिद्धांत बिल्कुल साफ है कि सिर्फ दोषपूर्ण जांच के आधार पर ही आरोपी व्यक्तियों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभियोजन पक्ष द्वारा इकट्ठा किए गए बाकी सबूतों, जैसे चश्मदीद गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह पर विचार करना न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस न्यायालय का हमेशा से यही रुख रहा है कि आरोपी, अभियोजन एजेंसी द्वारा की गई दोषपूर्ण जांच के आधार पर बरी होने का दावा नहीं कर सकते। चूंकि पूरे विचारण के दौरान अपील करने वालों का नाम लेने में चश्मदीद गवाहों का बयान एक जैसा रहा है, इसलिए हमें लगता है कि आरोपी व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त पुष्टि मौजूद है।"

49. अपीलकर्ता के अधिवक्ता की दलील का आखिरी हिस्सा यह है कि आरोपी-राजेंद्र को चाकू से चोट पहुँचाने का काम सौंपा गया था, जबकि मौजूदा अपीलकर्ता और अन्य आरोपियों को लाठी दी गई थी। चूंकि ज्यादातर चोटें चाकू से लगी थीं, इसलिए लाठी से लगी चोटों के लिए अपीलकर्ता को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अपीलकर्ता के अधिवक्ता की यह दलील पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित है और इसमें कोई दम नहीं है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



50. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने नौ चोटों का ज़िक्र किया है। अंदरूनी जाँच में डॉक्टर को खोपड़ी में खून का थक्का मिला। झिल्लियाँ सूजी हुई और फटी हुई थीं। खून का थक्का मौजूद था; दिमाग सूजा हुआ और फटा हुआ था और उसमें भी खून का थक्का था; मुँह, दाँत और जीभ टूटे हुए थे। डॉक्टर ने खास तौर पर राय दी कि चोट संख्या 4, 5 और 7 को छोड़कर, बाकी चोटें लाठी के वार या किसी कुंद चीज़ से लगी थीं।

51. इसके अलावा, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 148 और 149 के तहत इस मामले में शामिल किया गया है। वह उस गैर-कानूनी भीड़ (गैर-कानूनी जमावड़ा) का हिस्सा था जिसका मकसद आपराधिक बल का इस्तेमाल करके बिदेशी (मृतक) को खत्म करना था। इसलिए, गैर-कानूनी भीड़ का सदस्य होने के नाते, वह उस मकसद को पूरा करने के दौरान किए गए अपराध, यानी IPC की धारा 302 के तहत अपराध का भी दोषी था।

52. इस मोड़ पर, हम संबंधित कानूनी प्रावधानों का संक्षेप में जायज़ा लेंगे।

IPC की धारा 141 गैर-कानूनी जमावड़े (गैर-कानूनी जमावड़ा) को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि पाँच या उससे ज़्यादा लोगों के जमावड़े को गैर-कानूनी जमावड़ा माना जाता है, अगर उस जमावड़े में शामिल लोगों का साझा मकसद आपराधिक बल का इस्तेमाल करके कोई गैर-कानूनी काम करना हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



IPC की धारा 148 घातक हथियारों के साथ दंगा करने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी घातक हथियार या ऐसी किसी चीज़ के साथ दंगा करने का दोषी पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर करने से मौत हो सकती है, उसे तीन साल तक की कैद (किसी भी तरह की), जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं।

IPC की धारा 149 कहती है कि गैर-कानूनी जमावड़े का हर सदस्य उस अपराध का दोषी होगा जो साझा मकसद को पूरा करने के दौरान किया गया हो। आईपीसी की धारा 149 में यह भी कहा गया है कि अगर गैर-कानूनी जमावड़े का कोई सदस्य उस जमावड़े के साझा मकसद को पूरा करने के दौरान कोई अपराध करता है, या ऐसा अपराध करता है जिसके बारे में जमावड़े के सदस्यों को पता था कि उस मकसद को पूरा करने के दौरान ऐसा अपराध होने की संभावना है, तो उस अपराध को करने के समय उसी जमावड़े का सदस्य रहने वाला हर व्यक्ति उस अपराध का दोषी माना जाएगा।

53. इस प्रकार, यह IPC की धारा 302 के तहत हत्या का मामला है; गैर-कानूनी भीड़ का हर सदस्य आईपीसी की धारा 302/149 के तहत अपराध करने का दोषी होगा।

54. कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2012) 11 एस सी सी237 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा:

अब यह कानून अच्छी तरह से तय हो चुका है कि आईपीसी की धारा 149 तब लागू होगी जब किसी गैर-कानूनी सभा का कोई सदस्य उस सभा के साझा मकसद को पूरा करने के लिए कोई अपराध करता है, या जब सभा के सदस्यों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को पता होता है कि उस मकसद को पूरा करने के दौरान अपराध होने की संभावना है; ऐसे में, अपराध करते समय सभा का सदस्य रहा हर व्यक्ति उस अपराध के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार और दोषी माना जाएगा। आईपीसी की धारा 149 गैर-कानूनी सभा के सदस्यों पर उस सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा साझा मकसद के तहत किए गए गैर-कानूनी कामों के लिए परोक्ष जिम्मेदारी तय करती है। यह सिद्धांत सभा के हर सदस्य को अपराध का दोषी बनाता है, यदि वह अपराध सभा के किसी सदस्य द्वारा उसके साझा मकसद को पूरा करने के लिए किया गया हो, या सदस्यों या सभा को पता हो कि उस मकसद को पूरा करने के दौरान अपराध होने की संभावना है।

"जब किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 149 के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही हो, तो चोट पहुँचाने या न पहुँचाने की बात मायने नहीं रखती। न्यायालय को मुख्य रूप से यह देखना होता है कि क्या आरोपी गैर-कानूनी भीड़ का सदस्य था, न कि यह कि उसने असल में अपराध में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया या नहीं।"

55. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'विनुभाई रणछोड़भाई पटेल बनाम राजीवभाई दुदाभाई पटेल' (2018) 7 एस सी सी 743 मामले में फिर से यह बात दोहराई कि धारा 149 कोई अलग अपराध नहीं बनाती, बल्कि यह केवल गैर-कानूनी भीड़ के सभी सदस्यों की 'विकेरियस लायबिलिटी' (पयास देयता) यानी सामूहिक जिम्मेदारी तय करती है, जो उस भीड़ के साझा मकसद के तहत किए गए कामों के लिए होती है। न्यायालय ने आगे यह भी कहा:

"ऐसे मामलों में जहाँ गैर-कानूनी भीड़ में शामिल बहुत से आरोपियों पर एक या ज़्यादा लोगों पर हमला करने और उनकी हत्या करने का आरोप हो, वहाँ यह ज़रूरी नहीं है कि हर आरोपी ने जानलेवा चोट या कोई भी चोट पहुँचाई

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हो। ऐसे मामलों में गैर-कानूनी भीड़ के सदस्यों को 'विकेरियस लायबिलिटी' (दूसरों के काम के लिए ज़िम्मेदारी) के आधार पर सज़ा देने के लिए IPC की धारा 149 लागू करना ज़रूरी है, भले ही उन पर जानलेवा चोट पहुँचाने का आरोप न हो, बशर्ते रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत इसकी पुष्टि करते हों। ऐसी गैर-कानूनी भीड़ में आरोपी की मौजूदगी ही उसे हमले के शिकार व्यक्ति की मौत के लिए आईपीसी की धारा 149 के तहत 'विकेरियस लायबिलिटी' के लिए ज़िम्मेदार ठहराने के लिए काफी है, बशर्ते आरोपियों को यह बताया गया हो कि उन्हें IPC की धारा 302 के तहत सज़ा-योग्य अपराध के लिए आईपीसी की धारा 149 के तहत 'विकेरियस लायबिलिटी' का सामना करना पड़ सकता है। धारा 149 को सही ढंग से लागू न करने की वजह से बहुत से अपराधी अपराध करके बच निकलते हैं।"

56. कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2012) 11 एस सी सी 237 और विनूभाई रणछोड़भाई पटेल बनाम राजीवभाई दुदाभाई पटेल (उपरोक्त) मामलों में दिए गए फैसलों का पालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नित्यानंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) 9 एससी आर 37 मामले में किया है।

57. अपीलकर्ता के अधिवक्ता की दलील के आखिरी हिस्से के बारे में, जिसमें कहा गया है कि घटना रात में हुई थी और आरोपी को पहचानने के लिए रोशनी काफी नहीं थी, यह ध्यान दिया जा सकता है कि पीडब्लू-2, श्रीमती मुर्ता ने अपनी मुख्य गवाही में साफ तौर पर कहा है कि वह चाँदनी रात थी। इसके अलावा, पीडब्लू-3 शंकर ने अपनी जिरह में कहा है कि वह बिना टॉर्च की रोशनी के आरोपी को देख पा रहे थे। पीडब्लू-4, राम नरेश ने अपनी जिरह में कहा है कि जब वह घटना वाली जगह के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि आरोपी मृतक के साथ मारपीट कर रहे थे। साथ ही, पीडब्लू-2, श्रीमती मुर्ता (जिन्होंने सबसे पहले सूचना दी थी), पीडब्लू-3 शंकर, पीडब्लू-4 राम नरेश

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और सभी आरोपी या तो रिश्तेदार हैं या एक ही गाँव में रहते हैं और वे एक-दूसरे को जानते थे। चूँकि गवाह आरोपी को जानते थे, इसलिए उन्हें आरोपी की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

58. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनवर हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1981 एससी 2071 मामले में यह कहा था:

"अगर रोशनी कम भी हो, तो भी कोई गवाह उस व्यक्ति की पहचान कर सकता है जिसे वह अच्छी तरह जानता हो या जिसके साथ उसके करीबी संबंध हों। वह उसकी आवाज़, शारीरिक बनावट आदि से पहचान कर सकता है। इसलिए, पीडब्लू-8 के इस दावे को खारिज करने का कोई कारण नहीं है कि उसने अपीलकर्ता को पहचाना था।"

59. दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2008) 11 एस सी सी 425 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी गवाह के लिए कम रोशनी में भी हमलावर की पहचान करना संभव है, अगर वह हमलावर की आवाज़, चाल-ढाल, शारीरिक बनावट आदि से परिचित हो या उसके साथ करीबी संबंध रखता हो।

60. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, अपीलकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क कि अपीलकर्ता को पहचानने के लिए रोशनी कम थी, बेबुनियाद है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



61. यह एक भयानक हत्या थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि मृतक पर बेरहमी से हमला किया गया था। चोटों की गंभीरता हमलों की क्रूरता को साफ तौर पर दिखाती है।
62. हमने पीडब्लू-2 श्रीमती मुर्ता, पीडब्लू-3 शंकर और पीडब्लू-4 राम नरेश की गवाही की सावधानीपूर्वक जांच और समीक्षा की है और हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने उनका सही ढंग से मूल्यांकन और विश्लेषण किया है।
63. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपना मामला बिना किसी उचित संदेह के सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।
64. इसलिए, आपराधिक अपील खारिज की जाती है।
65. अपीलकर्ता साँवरें जमानत पर है। उसका जमानत बंधपत्र रद्द कर दिया गया है और जमानतदारों को बरी कर दिया गया है। उसे निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा सुनाई गई सज़ा को पूरा करने के लिए चार हफ्ते के अंदर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे।
66. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक कॉपी संबंधित न्यायालय को पालन के लिए भेजे और पालन की रिपोर्ट दो महीने के अंदर इस न्यायालय में जमा करे।

(माननीय न्यायमूर्ति चावन प्रकाश)

(माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र धारी सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक : 02 फरवरी, 2026

इशरत

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”